भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3790**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
टैरिफ में बढ़ोत्तरी

3790. **श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:**
क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिक्स सदस्य देशों से आयात पर विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और हरित प्रौद्योगिकियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए टैरिफ या बढ़ाए गए टैरिफ पर ध्यान दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:
(ख) क्या ऐसे उपायों से भारत के व्यापार संतुलन, आपूर्ति शृंखला या निर्यात पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार अन्य ब्रिक्स देशों पर टैरिफ से प्रभावित क्षेत्रों में अमेरिका में भारत की बाजार पहुँच बढ़ाने के अवसरों का मूल्यांकन कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ब्रिक्स सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को कायम रखते हुए भारत के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए राजनयिक रूप से या विश्व व्यापार संगठन, जी20 या आईपीईएफ जैसे व्यापार मंचों के माध्यम से बातचीत करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) जनवरी 2025 से अमेरिका ने सभी देशों से आयात पर अलग-अलग दरों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए हैं। ये टैरिफ व्यापार घाटे, डग्स की अवैध आवाजाही, सीमा सुरक्षा आदि से संबंधित कारणों का हवाला देते हुए लगाए गए हैं। तथापि, अब तक ब्रिक्स की सदस्यता के आधार पर अमेरिका द्वारा कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया गया है।

(ख) से (घ) सरकार भारत से निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ के प्रभाव की निरंतर निगरानी कर रही है। सरकार अमेरिका द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ के प्रभाव के आकलन हेतु निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए संपर्क में है। सरकार किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और उद्योग के सभी वर्गों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को अत्यधिक महत्व देती है।

*****